

## सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खेल प्रशासन के राजनीतिकरण की नदि

### प्रलिस के लयः

[भारतीय एमेच्योर कबडडी महासंघ](#), [भारतीय सर्वोच्च न्यायालय](#), [भारतीय ओलंपिक संघ](#), [राज्य वषिय](#), [भारतीय राष्ट्रीय खेल संहति](#)

### मेन्स के लयः

खेल प्रशासन में न्यायिक नगरानी, भारतीय खेल महासंघों में राजनीतिकरण, खेल प्रशासन

[स्रोत: द हद्वि](#)

### चर्चा में क्यों?

[भारतीय सर्वोच्च न्यायालय](#) ने युवा मामले और खेल मंत्रालय को नरिदेश दिया है कविह AKFI के IKF द्वारा नलिंबन के बीच भारत की एशियाई कबडडी चैपयिनशपि 2025 में भागीदारी सुनशिचति करे ।

- यह नरिदेश [भारतीय एमेच्योर कबडडी महासंघ \(AKFI\)](#) को अंतरराष्ट्रीय कबडडी महासंघ (IKF) द्वारा नलिंबति कयि जाने के बाद आया है, जसिमें न्यायालय ने खेल प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप और नौकरशाही नयितरण की आलोचना की है ।

### IKF द्वारा AKFI को नलिंबति क्यों कयि गया?

- AKFI:** AKFI भारत में कबडडी के लयि सर्वोच्च शासी नकिय है । यह राष्ट्रीय, इनडोर, बीच और सरकल स्टाइल सहति सभी प्रकार की कबडडी को नयितरति करने के साथ टूरनामेंट आयोजति करने, टीमों का चयन करने एवं खेल के वकिस की देखरेख करने में प्रमुख भूमिका नभिता है ।
  - मुख्यालय: जयपुर, राजस्थान
  - संबद्धता: भारतीय ओलंपिक संघ (IOA), एशियाई कबडडी महासंघ (AKF), और अंतरराष्ट्रीय कबडडी महासंघ (IKF) । AKFI IKF और AKF से प्राप्त दशिा-नरिदेशों का पालन करता है ।
  - मान्यता: इसे युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है ।
- AKFI के संबंध में चतिाएँ:** AKFI पर अपारदर्शी चुनाव, कुप्रबंधन एवं राजनेताओं द्वारा एकाधिकार के आरोप लगते हैं जसिसे भाई-भतीजावाद और नषिपक्ष प्रतनिधित्व को लेकर चतिाएँ बढ़ गई हैं ।
- दिल्ली उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप:** AKFI प्रबंधन की चतिाओं के बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति (सेवानवृत्त) एस.पी. गर्ग को इसके मामलों की देखरेख के लयि प्रशासक नयिकृत कयि ।
- AKFI का नलिंबन:** IKF ने प्रशासनिक मुद्दों पर AKFI को नलिंबति कर दिया, जसिमें नरिवाचति नकिय की अनुपस्थति का हवाला दिया गया, जसिसे भारत की अंतरराष्ट्रीय कबडडी भागीदारी खतरे में पड़ गई ।
  - IKF ने आश्वासन दिया कथिर्द प्रशासक के स्थान पर कोई नरिवाचति नकिय नयिकृत कयि जाता है तो AKFI की संबद्धता बहाल कर दी जाएगी तथा भारत, ईरान चैपयिनशपि में भाग ले सकेगा ।

**नोट:** वर्ष 2004 में स्थापति और जयपुर में मुख्यालय वाला IKF, कबडडी का वैश्विक शासी नकिय है, जसिके 24 संबद्ध देश (भारत सहति) हैं ।

### सर्वोच्च न्यायालय का आदेश:

- सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति (सेवानवृत्त) एस.पी. गर्ग को दसिंबर 2023 के चुनावों से नव नरिवाचति नकिय को प्रभार सौंपने का नरिदेश दिया ।
  - न्यायालय ने आगामी एशियाई कबडडी चैपयिनशपि 2025 के कारण इसकी तात्कालिकता पर बल दिया तथा AKFI की शासी संस्था को

तत्काल टीमों का चयन करने, प्रशिक्षण शिविरों की व्यवस्था करने तथा टूर्नामेंट में भारत की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

- न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि प्राधिकार हस्तांतरण का तात्पर्य AKFI चुनावों के समर्थन से नहीं है तथा इससे संबंधित मुद्दे नरिणय के लिये खुले हैं।

## खेल प्रशासन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की क्या चिंताएँ हैं?

- **राजनीतिकरण:** पूर्व राजनेता और नौकरशाह खेल निकायों पर हावी हो जाते हैं, जिससे **खिलाड़ी कम प्रभावी** हो जाते हैं।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि खेल संघों में सुधार तब होता है जब राजनेता या नौकरशाही द्वारा नियुक्त लोगों के बजाय खिलाड़ी ज़िम्मेदारी संभालते हैं।
- **कुप्रबंधन:** अपारदर्शी चुनाव प्रक्रिया, वित्तीय अनियमितताओं और कुछ व्यक्तियों द्वारा एकाधिकार के आरोप सामने आए हैं।
  - AKFI जैसे संघ उचित रूप से नरिवाचित शासी निकायों के बनिा कार्य करते हैं तथा खेल मानदंडों का उल्लंघन करते हैं जो **भारतीय राष्ट्रीय खेल संहिता 2011** के अनुरूप नहीं हैं।
- **नियंत्रण और संतुलन न होना:** स्पष्ट नगिरानी या जवाबदेही के अभाव में, खेल निकाय पारदर्शिता के बनिा कार्य करते हैं जैसा **कविरष 2010** के **राष्ट्रमंडल खेलों** में स्पष्ट हुआ, जहाँ **केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)** ने 14 परियोजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं की रिपोर्ट की थी।
- **एथलीटों पर प्रभाव:** प्रशासनिक अक्षमताओं के कारण टीम चयन, प्रशिक्षण और टूर्नामेंट में भागीदारी में देरी से एथलीटों को नुकसान होता है।
  - एथलीटों को **यौन उत्पीड़न** का सामना करना पड़ता है लेकिन कमज़ोर शिकायत प्रणाली तथा देरी से की जाने वाली कार्यवाही के कारण इनको असुरक्षित महसूस होता है इसीलिये इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है।
- **खेल अवसंरचना:** चूंक खेल, **राज्य का वषिय** है इसलिये पूरे भारत में इससे संबंधित अवसंरचना विकास के लिये कोई एक समान दृष्टिकोण नहीं है।

## भारत की राष्ट्रीय खेल संहिता 2011 क्या है?

इसे जानने के लिये यहाँ क्लिक करें: [भारतीय राष्ट्रीय खेल संहिता 2011](#)

## आगे की राह

- **लेखापरीक्षा:** खेल महासंघों की मान्यता से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिये राजनयिक माध्यमों का प्रयोग करना तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार और नहिति स्वार्थों को समाप्त करने के लिये **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)** एवं **इंटरपोल** के तहत जाँच सुनिश्चित होनी चाहिये।
  - सभी खेल महासंघों को संचालित करने के लिये स्पष्ट कानून और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ एक **केंद्रीय नियामक निकाय** की आवश्यकता है जिससे पारदर्शी शासन एवं नषिपक्ष तथा जवाबदेह प्रशासन के लिये सख्त नगिरानी सुनिश्चित हो सके।
- **एथलीटों को सशक्त बनाना:** पारदर्शिता और जवाबदेहता के क्रम में नरिणय लेने में एथलीटों की सक्रिय भूमिका होनी चाहिये।
  - ओलंपिक चार्टर का पालन करना चाहिये जिसके तहत **राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों** (जैसे, भारत में IOA) में एथलीट प्रतिनिधियों को अनविरय बनाया गया है।
- **महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना:** लैंगिक समानता सुनिश्चित करने, कोटा स्थापित करने तथा खेल प्रशासन कॅरियर में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के क्रम में सुरक्षित, समावेशी वातावरण विकसित करना चाहिये।

?????? ???? ?????:

प्रश्न: भारतीय खेल महासंघों में राजनीतिक हस्तक्षेप तथा नौकरशाही नियंत्रण के प्रभाव का परीक्षण कीजिये।

### UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????

प्रश्न. खिलाड़ी ओलंपिकस में व्यक्तगत वजिय और देश के गौरव के लिये भाग लेता है; वापसी पर वजिताओं पर वभिन्न संस्थाओं द्वारा नकद प्रोत्साहनों की बौछार की जाती है। प्रोत्साहन के तौर पर पुरस्कार कार्यवधिके तर्काधार के मुकाबले, राज्य प्रायोजित प्रतिभा खोज और उसके पोषण के गुणावगुण पर चर्चा कीजिये। (2014)